

आज बेबाक

बेटी बचाओ आंदोलन की तर्ज पर विधायक बचाओ आंदोलन भी चलाया जाए। इसका खर्च सरकार वहन करे। बेचारे गरीब राजनैतिक दलों को आखिर कब तक अपने विधायकों को फाइव स्टार होटलों में ऐश करने का खर्च उठाना पड़ेगा? विधायक जनता का प्रतिनिधि बाद में है पहले वह राजनैतिक पार्टियों की संपत्ति होता है। दो कौड़ी की लोग करोड़ों में जो बिकते हैं। वैसे कितने भी परदे में रखो ब्रिक्काड माल बिक ही जाता है। वो गाना है-रहे कोई सौ परदों में डरे शरम से, लाख चुपए नजारे अपने सनम से, आ ही जाता है न जिस पर दिल आना होता है...

खास खबर

लोकसभा में कांग्रेस सांसदों और मार्शल के बीच धक्का-मुक्की

नई दिल्ली ए.। महाराष्ट्र के मुद्दे के विरोध के दौरान कांग्रेस सांसदों और मार्शल के बीच टकराव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिहारी ने कहा कि यह पहली बार है जब मैंने सदन को हंगामे के बाद स्थगित कर दिया है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि सदन चले और बहस होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, 3 संदिग्ध गिरफ्तार

नई दिल्ली ए.। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को बड़े आतंकी मोहकूल का पंछाफंड किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। स्पेशल सेल ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संदिग्धों के पास से आईसीडी भी बरामद किया है। स्पेशल सेल के डीएसपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया है कि असम के गोलपारा से तीन व्यक्ति ईस्लाम, रणजीत अली और जमाल को गिरफ्तार किया गया है।

भोपाल समेत पूरे प्रदेश में कम होगी जुर्माने की राशि

भोपाल। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद नए प्रावधान 9 सितंबर से लागू हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इन्हें अभी तक लागू नहीं किए। प्रदेश के नियम बनने के कारण केंद्र के प्रावधान कोर्ट के मार्फत लागू हो रहे हैं। दरअसल, परिवहन विभाग प्रदेश में जुर्माने की राशि में कमी लाने अपने नियम जारी करेगा। नियम लागू होने के बाद हेलमेट न लगाने से लेकर बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने सहित सभी तरह के जुर्माने में करीब आधा जुर्माना तय कर दिया जाएगा।

गरमा-गरम

भाष्य स मुक्त करें- लोकप्रिय हो जायें



व्यापम घोटाले से जुड़े 14वें केस में फैसला, पहली बार सभी आरोपियों को सजा हुई

30 दोषियों को 7-7 साल और दलाल त्यागी को 10 साल की सजा

दोषियों में 12 फर्जी परीक्षार्थी और 7 दलाल शामिल, सभी को सेंट्रल जेल भेजा गया

व्यापम के 7 केस में जांच जारी, 143 में चार्जशीट दाखिल, करीब 1000 परीक्षार्थी आरोपी

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। व्यापम की पुलिस आश्चर्य भरी परीक्षा 2013 के मामले में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 30 दोषियों को 7-7 साल, जबकि दलाल प्रदीप कुमार त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दलाल त्यागी को मुख्य सूत्रधार माना। पिछले सप्ताह (गुरुवार को) सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले में सभी शेष पृष्ठ 7 पर

की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 30 दोषियों को 7-7 साल, जबकि दलाल प्रदीप कुमार त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दलाल त्यागी को मुख्य सूत्रधार माना। पिछले सप्ताह (गुरुवार को) सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले में सभी शेष पृष्ठ 7 पर



इन्हें सुनाई 7-7 साल की सजा

अदालत ने राहुल पांडे, आशीष कुमार पांडे, कुलविजय, अभिषेक कटियार, सुश्रुत सपसेना, प्रभाकर शर्मा, नैरज उर्फ टिप्पू, अजिता वायस, अजय सक्सेना, धरमेश साहू, फूलकुमार, देवेंद्र खड्डू, अजित चौधरी, लुप्रेट सिंह तोमर, स्तोत्र शर्मा, चंदपाल कश्यप, प्रजाब साहू, रविशंकर, नवीस गजट, मुकेश साहू, अरुण गुर्जर, उदयभानु साहू, दानिश धाक?, अतनंद साहू, एवेंडर खड्डू तोमर, सुदीप शर्मा, अजय प्रताप साहू, कल्याण साहू सिकंदरवार, कुलवीर सिंह जाट और राजवीर सिंह उर्फ बंटी को 7-7 साल की सजा सुनाई।

सजा का आधार: 450

दस्तावेज, 90 गवाहों के बयान

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक स्वीट् डिनकर ने बताया कि व्यापम की वह परीक्षा 15 सितंबर 2013 को हुई थी। वड़वाड़ी की शिक्षा के बाद गोपाल और दत्तिका के सेटर्स पर कार्यवाई के दौरान 31 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नागालों की जांच एसटीएफ से सीबीआई को सौंपी गई थी। अदालत ने 450 से ज्यादा दस्तावेज और 90 गवाहों के बयान लिए गए।

महाड्रामा पर सुप्रीम फैसला आज

फ्लोर टेस्ट 30 को या पहले, आज 10:30 बजे आएगा निर्णय

नवप्रदेश संवाददाता

नई दिल्ली/मुंबई। महापट्ट में चल रहे सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंगलवार को आएगा। फंडणवीस सरकार को विश्वासमत कब पेश करना होगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि शनिवार को सुबह महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा को सरकार बनाने का न्योता देकर देवेन्द्र फंडणवीस को मुख्यमंत्री व अजित पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। साथ ही फंडणवीस को विश्वास मत (फ्लोर टेस्ट) के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था। लेकिन इस चिन्हा पर सवाल उठाते हुए शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी ने शपथ ग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर गुरुवार से सुनवाई जारी है।

सोमवार को तीन जजों-जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस अशोक भूषण व जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सभी की दलीलों व मंगाए गए दस्तावेजों पर गौर करने के बाद बाद कहा कि मामले शेष पृष्ठ 7 पर



ये कहा तीन जजों की बेंच ने

मामले के हर पहलू पर विचार करना होगा राज्यपाल के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ऐसे मामलों में 24-48 घंटे का ही दिया जाता है समय

एनसीपी, सेना व कांग्रेस के पास 162 विधायक, ती शपथ

एनसीपी, शिवसेना व कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि उनके पास बहुमत है। तीनों दलों के नेता होटल हयात में अपने शीर्ष नेताओं के सामने एकत्र हुए। एनसीपी, कांग्रेस व शिवसेना के विधायकों ने महावििकास आघाड़ी के प्रति निष्ठा की शपथ भी ली। इस दौरान शिवसेना प्रमुख उदय ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार व महाराष्ट्र कांग्रेस के शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। शेष पृष्ठ 7 पर

किसने क्या दी दलील : सुप्रीम कोर्ट लाइव

भाजपा: वरिष्ठ वकील गुणाल रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल को अजित पवार की ओर से दिया गए पत्र में एनसीपी के 54 विधायकों के भाजपा को समर्थन संबंधी हस्ताक्षर हैं। राज्यपाल का काम पत्र की जांच पड़ताल करना नहीं है। अजित नारायण विधानसभा में एनसीपी के विधायक दल के नेता है तो उनकी ओर से दिया गया पत्र ही अधिकृत है।

कोर्ट : इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोहतगी को कहा कि यदि आपका पास बहुमत है तो उसे सिद्ध क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जवाब दिया कि क्या आप आज

फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि ऐसे मामलों में 24 घंटे का समय ही दिया जाता है। भाजपा: रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल ने जो 30 नवंबर की तारीख दी है उसी दिन फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। कोर्ट वकीलों के फेर में न जाए। विधानसभा के कामकाज में हस्तक्षेप न करें। सिर्फ 5 दिन का समय बचा है तो फिर इतनी जल्दी क्यों।

उपमुख्यमंत्री : अजित पवार की ओर से पेश वकील नमिंदर सिंह ने भी रोहतगी वाले ही तर्क दिए। वह भी कहा कि कहा अजित पवार यानी ही एनसीपी।

गठबंधन के तीनों दलों को लगी फटकार

शिवसेना : वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। 22 नवंबर को शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों दल एकसाथ हैं। सिब्बल ने खवाल किया कि सुबह 5 बजे खटपटी शासन क्यों बटाटा गया और 8 बजे शापथ क्यों दिलाई गई। शपथ ग्रहण प्रक्रिया का खुलासा होना चाहिए।

एनसीपी: एडवोकेट अभिषेक गनु सिधौरी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए पत्र दिन क्यों चाहिए। वह 24 घंटे में ही जाना चाहिए। जो पत्र अजित पवार ने दिया है उसमें सिर्फ विधायकों के हस्ताक्षर हैं लेकिन वे एनसीपी के साथ नहीं हैं। कोर्ट : टेकते हुए कहा कि अब बाकी का कुछ मत बताइए, फ्लोर टेस्ट पर बात करें। शेष पृष्ठ 7 पर

पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी पंचतत्व में विलीन

इंदौर (हाटपिपल्वा)

पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने छोटे भाई योगेश जोशी के साथ मुख्यानि दी। अंतिम यात्रा सोमवार दोपहर उनके निजी निवास से निकाली गई। अंतिम विदाई में केंद्रीय मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर, प्रदेशाध्यक्ष राकेशसिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, सांसद नंदकुमारसिंह चौहान, विधायक

चेतन कश्यप, भाजपा महासचिव कैलाश बिजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री कमल पटेल, ओमप्रकाश सखलेचा, राय सिंह सेंधव, नरेंद्र सिंह राजपुत, सुभाष शर्मा, उमेश शर्मा, पहाड़सिंह, राजेन्द्र वर्मा, दीपत तंवर, फूलसिंह चावड़ा सहित कई नेता और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। दो किमी अंतिम यात्रा मार्ग पर लोगों ने फूल बरसाकर शेष पृष्ठ 7 पर

अजित के खिलाफ केस बंद नहीं : एसीबी

मुंबई। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने

मुंबई। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने सेक्युरिटी सीएम अजित पवार को सिंचाई घोटाले में राहत मिलने की खबरों को अस्वीकार बताया है। कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद एसीबी ने कहा कि अजित पवार के खिलाफ आज कोई मामला बंद नहीं किया गया है। एसीबी ने कहा कि सिंचाई घोटाले से जुड़े 3 करोड़ 3 हजार टेंडरों को भी जांच चल रही है। उम्मीद है, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। बताया जा रहा है कि 9

मामलों में अजित पवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।

एसीबी ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट जांच के आदेश देगा या कुछ नए सबूत सामने आते हैं तो हम जांच करने के लिए तैयार हैं। एसीबी के डीजी परमबीर सिंह ने कहा, 'हम सिंचाई घोटाले से जुड़े 3 हजार टेंडरों को लेकर हुई शिकायतों की जांच कर रहे हैं। ये रोजमर्रा की जांच है जो बंद हुई है। जिन मामलों में पहले से जांच चल रही है, वे आगे भी जारी रहेंगे।

खाएंगे और खिलाएंगे भी : सुरजेवाला

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने टीवी कर कड़ा, बीजेपी-अजित पवार द्वारा महाराष्ट्र के प्रजातंत्र धीरहरण आख्या की असत्यित उजागर। एक नाजयज सरकार द्वारा एसीबी को सब मुकदमे बंद करने का आदेश। खाएंगे और खिलाएंगे भी, क्योंकि यह ईमानदारी के लिए जीरो टोलरेंस वाली सरकार है। मोदी है तो मुमकिन है।

आपराधिक लोगों के चुनाव लड़ने पर फैसला करे चुनाव आयोग : सुको

नई दिल्ली ए.। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि आपराधिक रेकॉर्ड वाले व्यक्तियों को पार्टी टिकट देने से राजनैतिक दलों को रोकने के बारे में पेश प्रतिवेदन पर सुविचारित आदेश पारित करें। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने बीजेपी नेता और अधिवक्ता अधिनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह आदेश दिया। उपाध्याय ने याचिका में निर्वाचन आयोग को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था जिससे कि राजनैतिक दलों शेष पृष्ठ 7 पर

तल्ख टिप्पणी

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार को लगाई कड़ी फटकार

‘दम घोटने से अच्छा बारूद से सबको उड़ा दो’

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने जल प्रदूषण के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली की हालत नरक से भी खराब है।

दिल्ली की हालत नरक से भी खराब है। आपकी नजर में किसी की जान की क्या कीमत है? आप लोगों से कितनी कीमत लेना चाहते हैं? आपको दिल्ली की कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। भारत में लोगों को जीवन इतना सस्ता नहीं है।

जस्टिस अरुण मिश्रा

नई दिल्ली। बेहद खफा नजर आ रहे सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह डाला कि दम घोटकर मारने से अच्छा है सबको एक साथ ही बारूद से उड़ा दिया जाए। यही नहीं कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली की सरकारें बताएं कि आखिर उन्हें खराब हवा के लिए लोगों को मुअवजा क्यों नहीं देना चाहिए। बता दें की बीएसआई ने देश के शेष पृष्ठ 7 पर



कोर्ट ने कहा है कि 10 दिन के अंदर शहर में एयर प्योरिफायर लगाने को लेकर खाका प्रस्तुत किया जाए

15 बारे बारूद ला उड़ा दीजिए सबको

सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, 'लोगों को गैस बैबर में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? इससे अच्छा है कि लोगों के एक साथ ही मार दिया जाए। 15 बारे में बारूद लें आइए और उड़ा दीजिए सबको। लोगों को इस तरह क्यों घुटना पड़े? जिस तरह से यहां ब्लेम गेम चल रहा है, मुझे आश्चर्य है।' कोर्ट ने जल प्रदूषण के मामले का भी संज्ञान लेते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों जांच करें कि दिल्ली का पानी पीने योग्य है या नहीं और उसके बाद सारे आंकड़ों कोर्ट के सामने पेश किए जाएं।

पंजाब और हरियाणा को कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से कहा हम लोगों के साथ ऐसे व्यवहार कैसे कर सकते हैं और लोगों को मरने के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है। बताइए कि हमारे आदेश के बाद भी पराली जलाने में बढ़ोतरी क्यों हुई है? क्या यह आपकी विफलता नहीं है? कोर्ट ने सख्ती से कहा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी महोदय, हम राज्य में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सारे क्रियाकलाप रुकवा देंगे। आप लोगों को ऐसे मरने नहीं दे सकते। दिल्ली की सांस फूल रही है। आप नियमों को लागू करने में सक्षम नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली के लोग कैसे मर रहे हैं।

पंजाब और हरियाणा कुछ नहीं कर रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से भी कहा कि पराली जलाने के मामले कैसे बढ़ गए। एससी ने कहा, 'आपने पराली जलाने को रोकने के लिए अच्छा काम किया तो ये मामले बढ़ कैसे गए? पंजाब और हरियाणा दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं। बेहद तल्ख नजर आ रहे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी से शेष पृष्ठ 7 पर

इसलिए इसका इलाज नहीं करा पाए। मेरे आस-पड़ोस के लोग मानते हैं कि मैं डायन हूं और मुझसे दूर रहते हैं।' लोगों की नफ़रत भरी निगाहों से बचने के लिए कुमारी घर के भीतर ही रहती हैं।

महानगरों का भाव

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नै में पेट्रोल का दाम बढ़कर क्रमशः 74.66 रुपये, 77.34 रुपये, 80.32 रुपये और 77.62 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इससे पहले चारों महानगरों में पेट्रोल का भाव 25 नवंबर 2018 को क्रमशः 74.84 रुपये, 76.82 रुपये, 80.38 रुपये और 77.69 रुपये प्रति लीटर था।

अपराधिक लोगों के चुनाव लड़ने पर

को अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाए जाने से रोक जा सके। पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'हम निर्वाचन आयोग को निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता (उपाध्यक्ष) के 22 जनवरी 2019 के प्रतिवेदन पर तीन महीने के भीतर निर्वाचन करे और इस संबंध में विस्तृत आदेशों को प्रारित करे।' शीघ्र अदालत ने इसी तरह की एक अन्य जनहित याचिका का 21 जनवरी के अन्तिम निर्णय करते हुए याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया।

न्यूज गैलरी

अर्जुनसिंह की प्रतिमा हटाने पर निगम मौन, शासन ने जल्द निर्णय के निर्देश दिए

भोपाल। लिंक रोड नंबर दो पर नानक पेट्रोल पंप के सामने से हटाई गई शहीद की प्रतिमा के स्थान पर राजनेता की प्रतिमा स्थापित करने पर हुए विवाद का हल जल्द निकालने निगम को शासन ने निर्देशित किया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद के प्रपौत्र के इस प्रतिमा विवाद में शामिल होने के बाद शासन स्तर से निगम के उच्चाधिकारियों को ये निर्देश मिले हैं। हालांकि निगम बावजूद इसके पूरी तरह से मौन है और सीधे निर्देश व कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। गौरतलब है कि आजाद के प्रपौत्र अमित तिवारी आजाद ने दिल्ली के एक्टिविस्ट के साथ जब भोपाल में आजाद प्रतिमा पर माल्यापण कर अर्जुनइक्षसह प्रतिमा का विरोध किया तभी इसका निराकरण करने के निर्देश हुए। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह के परिजनों और समर्थकों को भी इसका हल करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि आजाद के प्रपौत्र ने शासन को प्रतिमा पर निर्णय करने के लिए दो दिसंबर तक का समय दिया है। निगम अफसरों के साथ जिला प्रशासन के अफसरों को आशंका है यदि दो दिसंबर तक कोई निर्णय नहीं हुआ औ आजाद के प्रपौत्र ने धरना प्रदर्शन शुरू किया तो फिर निगम प्रशासन के साथ संबंधितों की राष्ट्रीय स्तर छवि खराब होगी। दरअसल 2012 में ट्रैफिक बाधा के नाम पर नानक पेट्रोल पंप के सामने रोड के बीच से शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा हटाकर रोड साइड में स्थापित की गई थी। अब उसी जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह की प्रतिमा स्थापित कर दी। इसपर ही आपत्ति और विवाद हो रही है।

दिग्विजय ने विधायकों की होटल परेड पर कसा तंज, बोले- विधानसभा सदन में होना चाहिए था ये काम

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र में विधायकों की होटल में परेड करने पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में फ्लोर टेस्ट विधानसभा में सदन के अंदर होता है. आपको बता दें कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अपने विधायकों की होटल में परेड की है, जिसमें 162 विधायक शामिल बताए जा रहे हैं. साथ ही दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि वैसे 14 दिनों का समय बहुमत साबित करने क्यों दिया है. यह साबित करता है खरीद फरोखत होनी है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि अजीत पवार क्यों भाजपा के साथ हैं, यह भी आज सामने आ गया है. 9 मामलों में ABC मुंबई से पाक साफ हो गए और कुछ बाकी हैं. दिग्विजय सिंह ने देवेद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम पहले कहते थे कि अजीत पवार जेल में चक्की पिसेंगे, लेकिन वही अब उप-मुख्यमंत्री बने और भ्रष्टाचार के दर्ज मामले भी वापस हो गए, उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस गलबंधन की बनेगी, क्योंकि गुरुग्राम में मौजूद 20 के विधायक भी कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे भगवान हैं. साथ ही दिग्विजय ने कहा कि पार्टी प्रमुख शरद पवार खुद कह रहे उनके साथ धोखा हुआ है. जबकि सुप्रिया सुले अच्छी नेता है और भविष्य उनका है. कांग्रेस ने गठबंधन को फैसला देर से किया, इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सोच समझकर कदम उठाती है. इस बार भी ऐसा ही हुआ है और कोई देर नहीं हुई है. यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्विटर हैंडल बदलने का बचाव किया. उन्होंने कहा कि इसमें क्या गलत है, हर व्यक्ति को ट्विटर हैंडल पर अपने बारे में लिखने का अधिकार है. पब्लिक सर्वेंट कांग्रेस में नहीं होते क्या.

सिंधिया के ट्विटर स्टेटस बदलने पर सियासत तेज

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर पूर्व सांसद और मंत्री की जगह समाजसेवी और क्रिकेट प्रेमी लिखा, सिंधिया बोले- महीने भर पहले ही बायो बदल लिया था

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर हैंडल पर अपना बायो बदल लिया है। उन्होंने सांसद और केंद्रीय मंत्री जैसे पूर्व पदों का जिक्र हटाकर खुद को समाजसेवी और क्रिकेट प्रेमी बताया है। इस बदलाव के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि, सिंधिया का कहना है कि ऐसा उन्होंने डिटेल को शॉर्ट करने के लिए किया है और वह एक महीने पहले ही ऐसा कर चुके थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया को वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। बताया जा रहा है कि सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही नाराज चल रहे हैं। प्रदेश में सिंधिया को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया था। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया। चुनाव में जैसे ही कांग्रेस को बहुमत मिला। कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवा दिया। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिंधिया प्रदेश की राजनीति से दूर हो गए थे। सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की



मांग उनके समर्थक मंत्री समय-समय पर करते आ रहे हैं। सिंधिया के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की अटकलें अगस्त-सितंबर में भी लगी थीं। वे कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सोनिया से मुलाकात की। इसके बाद सिंधिया को अध्यक्ष बनाने का फैसला फिर टाल दिया गया। अब सिंधिया जी के कांग्रेस से किनारा करने पर मध्यप्रदेश

के विधायकों कमलनाथ जी कहां भेजेंगे। वहीं, जिंदी जोया नाम की एक यूजर लिखती है कि भक्तों को अपनी मां ठीक से याद नहीं लेकिन अपने मामा के लौटने की झूठी खबर पर खुशी मनाने में मजा आ रहा था। विपन ठाकुर नाम के एक यूजर लिखते हैं कि दिल्ली में बैठे फूफा का अगर मन बन गया तो मामा तो आ ही जाएंग। एक और यूजर लिखा है कि एमपी के भावी उपमुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य

राज्य सरकार से नाराजगी की खबरें

सिंधिया मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में आई बाढ़ के समय वहां के गांव-गांव जाकर लोगों से मिले थे। अक्टूबर में सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद और प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों के लिए जल्द काम करने की मांग की थी। नवंबर में सिंधिया ने दतिया के लोगों की समस्याओं के बारे में कमलनाथ को पत्र लिखा था। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की इनमें से किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया।

सिंधिया जी बने समाजसेवी दे सकते हैं ये बयान.... कांग्रेस मुंबई आईपीएल के चक्र में भोपाल टेस्ट हार रही है...और भाजपा आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले न्यूज एजेंसी के जरिए इस कंट्रोवर्सी पर सफाई दी थी। कुछ देर पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। जिसमें लिखा है कि हास्यास्पद हंगाम मचा हुआ है, मैंने ट्विटर प्रोफाइल एक महीने पहले ही बदला है।

3 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य, मॉनीटरिंग की व्यवस्था ही नहीं की, माफियाओं के हाथ में पार्किंग

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। नगर निगम ने शहरभर में पार्किंग से सालाना तीन करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य तय किया, लेकिन मॉनीटरिंग की व्यवस्था ही नहीं की। स्थिति ये रही कि ठेका एजेंसी माइंडटेक ने काम ही पूरा नहीं किया। शहर की पार्किंग स्थानीय माफियाओं के हाथ में चली गई। अब भी यही स्थिति है। नगर निगम की पार्किंग सेल के पास कोई टीम ही नहीं है। इसका कोई कमांड सेंटर भी नहीं है। जिस जीआईएस आधारित पार्किंग निगरानी के दावे किए थे उसके लिए ठेका कंपनी ने भी कोई व्यवस्था नहीं की। इसका पूरा नुकसान निगम के साथ ही अव्यवस्थित पार्किंग के तौर पर आमजनता को हो रहा है। गौरतलब है कि अभी इस पूरी सेल में दो से तीन कर्मचारी है। उपायुक्त और अपर आयुक्त को इसका सह प्रभार दिया हुआ है। यानि निगम का अमला केबिन से कभी कभार ही



निकलता है। अफसर तो जांच करते ही नहीं हैं। ऐसे में शहरभर में अवैध पार्किंग का गोरखधंधा फलफूल रहा है। माइंडटेक कंपनी खुद पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली करने लगी है तो जहां काइ व्यवस्था नहीं है वहां पार्किंग माफिया अवैध वसूली कर रहा है। लोगों के वाहन असुरक्षित है, उनसे मनमाना पैसा लिया जा रहा और उन्हें अपमानित भी किया जा रहा है। यही वजह है कि तीन साल बाद

भी शहर में माइंडटेक ने महज 22 पार्किंग ही विकसित की है, जबकि शहर में इस समय करीब 80 जगह पर अवैध पार्किंग का गोरखधंधा चल रहा है। हर माह एक करोड़ रुपए की अवैध कमाई पार्किंग से की जा रही है। अपर आयुक्त मेहताबसिंह गुर्जर का कहना है कि हम पार्किंग व्यवस्था में कसावट के साथ ही अवैध वसूली पर रोक लगाने लगातार संबंधितों से बैठक कर रहे हैं। कार्रवाई भी होगी।

बस चलाते हुए सिगरेट पी तो निगम आयुक्त ने काट दिया 3 दिन का वेतन

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। नगर निगम आयुक्त विजय दत्ता ने भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड अंतर्गत संचालित मार्ग क्रमांक 306 हलालपुर से एम्स हॉस्पिटल जाने वाली मिडी बस के चालक पर की बड़ी कार्यवाही की। बस चालक परिचालन के दौरान सिगरेट पी रहा था। निगम आयुक्त दत्ता उसके सामने से गुजर रहे थे और उनकी निगाह चालक पर पड़ी। उन्होंने तत्काल बस रूकवाई। बीसीएलएल के सीईओ को जानकारी दी और तीन दिन का वेतन काटने की कार्रवाई कराई। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और जब



सार्वजनिक परिवहन का परिचालन किया जा रहा हो तो ये बड़ा अपराध है। मिडी बस क्रमांक एमपी 04 पी ए 3282 के चालक द्वारा गांधीनगर से एम्स की ओर जाते समय धूम्रपान करते हुए बस का संचालन कर रहा था चालक की लापरवाही देख विजय दत्ताए आयुक्त नगर

निगम द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सूचित किया और उक्त बस के चालक मुन्ना यादव की तीन दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये इसके साथ ही अन्य चालक को उक्त बस पर संचालन हेतु भेजा

मजहबी जलसा

ग्रीन कचरे से बन रही गैस, हो रहा फूड जोन में इस्तेमाल

दुनिया में अमन के लिए सामूहिक दुआ के साथ इज्तिमा का समापन

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। दुनिया में अमन के लिए सामूहिक दुआ के साथ आलमी 72वें तब्तीली इज्तिमा का समापन हो गया। इसी के साथ जमातों और अन्य लोगों का लौटना शुरू हो गया है। पुराने शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जो देर रात भीड़ कम होने तक जारी रहेगा। इज्तिमा में कई देशों की जमातों के साथ लाखों लोग आए थे। तीन दिन तक लोगों ने सिर्फ मजहब पर कुरआन के जानकार लोगों के बयान



सुने। इस बार 200 इज्तिमाई निकाह हुए। दिल्ली मरकज से आए मौलाना साअद साहब ने इन निकाहों की तकमील कर खुतबा सुनाया और इन सभी जोड़ों की निकाहों की दुआ की। पहले इज्तिमा के दूसरे दिन निकाह पढ़ाने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार यह व्यवस्था बदली है। इज्तिमा स्थल पर निकलने वाले कचरे से रोजाना 8 टन गैस बनाई जा रही है। पहली बार ग्रीन और क्लीन इज्तिमा की थीम के साथ यहां जोरो वेस्ट इज्तिमा के रूप में भी काम शुरू किया गया है। राज्य शासन की

ठेस अपशिष्ट प्रबंधन समिति के सदस्य इमिन्याज अली ने बताया कि वॉलंटियर्स ग्रीन कचरे को अलग से यहां एकत्र कर रहे हैं। शेडिंग के जरिए इसे 6 एमएम कामयाब जंदगी की दुआ की। पहले इज्तिमा के दूसरे दिन निकाह पढ़ाने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार यह व्यवस्था बदली है। इज्तिमा स्थल पर निकलने वाले कचरे से रोजाना 8 टन गैस बनाई जा रही है। पहली बार ग्रीन और क्लीन इज्तिमा की थीम के साथ यहां जोरो वेस्ट इज्तिमा के रूप में भी काम शुरू किया गया है। राज्य शासन की

इज्तिमा स्पेशल ट्रेन के प्रस्थान समय में परिवर्तन

सोमवार को भोपाल स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 02131 भोपाल-हरजत निजामुद्दीन इज्तिमा स्पेशल गाड़ी के पूर्व में घोषित प्रस्थान समय 22.50 में परिवर्तन किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अब यह गाड़ी आज भोपाल स्टेशन से 22.50 बजे के स्थान पर 22.00 बजे प्रस्थान करेगी। शेष समय सारणी यथावत रहेगी।

अफवाहों की जर्जर नाँव पर सवार भाजपा : अभय दुबे



अपडेट क्या किया कि निराश और नाउम्मीद भाजपा अफवाहों की जर्जर नाँव पर उम्मीदों का किनारा तलाशने लगी। दुबे ने बताया कि सच्चाई यह है कि भाजपा की महाराष्ट्र में प्रजातंत्र को पराजित कर लोकतंत्र की लूट की कलाई कल देश की सर्वोच्च अदालत में खुलने

षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। इसीलिए भाजपा देश का ध्यान महाराष्ट्र के मुद्दे से भटकाने हेतु माननीय सिंधिया जी के ट्वीटर अकाउंट को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। दुबे ने कहा कि लगातार बेनकाब हो रही भाजपा इतनी भयप्रस्त है कि वो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की प्रोफाईल इनफो को आधार बनाकर निराधार भ्रामक प्रचार करने लगी है। इससे अधिक शर्मनाक बात तो यह है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने यहां तक भ्रम फैलाया कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज मोदी जी से भी मिलने वाले हैं।

वाली है। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक सामूहिक याचिका लगाकर महाराष्ट्र में भाजपा द्वारा संविधान को रौंदे जाने के प्रमाण दिये हैं। साथ ही 154 विधायकों के अलग-अलग शपथ पत्र प्रस्तुत कर भाजपा के

आदर्श गांव चयन में रुचि नहीं ले रहे सांसद, छह माह में महज एक ने चुना गांव

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजनाओं में शामिल सांसद आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के सांसदों की रुचि नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि छह माह के कार्यकाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राकेश सिंह को छोड़कर प्रदेश के शेष सांसद अपने ही संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा गांव तलाश नहीं कर पाए हैं, जिसे तमाम सुविधाएं पहुंचाकर आदर्श बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक सांसद को पांच गांव की जिम्मेदारी लेने को कहा है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सिंह ने भी अब तक एक ही गांव चुना है। इसका बदला है। इज्तिमा स्थल एवं ग्रामीण विकास विभाग तक पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कार्यकाल में देशभर के सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव



चुनने और उन्हें तकनीकी, सांस्कृतिक रूप से आदर्श बनाने के निर्देश दिए थे। इस बार प्रधानमंत्री ने प्रत्येक सांसद को पांच गांव गोद लेकर अपने कार्यकाल में उन्हें आदर्श ग्राम में बदलने को कहा है। यह निर्देश मई 2019 में दिए गए थे, लेकिन प्रदेश में इन निर्देशों का असर देखने को नहीं मिल रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तक अभी एक सांसद का प्रस्ताव पहुंचा है। सूत्र बताते हैं कि

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने जबलपुर के ग्राम घाना को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चुना है। इसके अलावा किसी भी सांसद ने अभी तक विभाग को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। जबकि मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों में से 28 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी।